'विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, बहस करते तो 5 साल की सच्चाई सामने आ जाती'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में अपनी सरकार के दो साल के काम की रिपोर्ट कार्ड रखते हुए टिप्पणी की

जयपुर, 21 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने आने वाले समय की कार्ययोजना बजट के रूप में रखने के साथ ही पहली बार सदन में अपनी सरकार के दो साल का रिपोर्ट कार्ड रखा था। शर्मा ने शनिवार को सदन में कहा कि हर सरकार का दायित्व है कि वह हर साल अपने कार्य का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने अपने दोनों वर्षों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए 2 साल बनाम 5 साल का प्रतिवेदन सदन में रखा, लेकिन विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वे बहस करते तो 5 साल की सच्चाई जनता के सामने आ जाती।

- मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में 626 ऐसी घोषणाएं कीं, जिन पर काम शून्य रहा, ये सब लोक लुभावन घोषणाएं थीं।
- मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी 90 प्रतिशत बजट घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी हो गई हैं, और 80 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं या शुरु हो चुकी हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को विधानसभा में दो साल के कामकाज का जवाब दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 626 घोषणाएं ऐसी की गईं, जिन पर काम शून्य रहा, यानी केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए लोकलुभावन वादे कर दिए गए और 450 करोड़ रुपये की लागत से 2000 पायलट ड्रोन देने, 400 करोड से चार माइस सेंटर बनाने, 125 करोड़ से पांच गोल्फ कोर्स बनाने और 125 करोड़ से विश्वकर्मा एसएमई टावर बनाने जैसी घोषणाओं पर 'काम ज़ीरो' हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए, राज्य सरकार ने पिछली सरकार की योजनाओं को न केवल जारी रखा है, बल्कि उनकी प्रभावशीलता को भी बढ़ाया है।

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम समय में पेंशन में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं कीं, जबकि हमारी सरकार ने पहले ही साल से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया और अब इसे बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। इसके अलावा, 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 10 लाख से अधिक नए पेंशनर्स जोड़े गए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के 2 वर्षों के मुकाबले 3 गुना अधिक हैं।

शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिल रहे नि:शुल्क खाद्यान्न के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया "गिवअप" अभियान एक जन आंदोलन बना। इसमें लगभग 54 लाख व्यक्तियों ने स्वैच्छिक गिवअप किया और 27 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम ईकेवाईसी के जरिए हटाए गए। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न से वंचित लगभग 72 लाख पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़कर उनका हक दिलाने का कार्य भी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने दो साल में 3 लाख 41 हजार 347 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया है, जो गत सरकार के पूरे पांच साल की तुलना में डेढ़ गुना है। हमने 185 राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण किया है, जो गत सरकार से सवा तीन गुना है और चार गुना अधिक 21 नये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। हमने विद्यार्थियों को 88 हजार 724 टेबलेट और लेपटॉप वितरण किए, जबकि पिछली सरकार ने एक भी टेबलेट या लेपटॉप बच्चों को नहीं दिया। वहीं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत, राज्य सरकार अपने 2 वर्षों में ही 35 हजार से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर चुकी है, जो कि पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्षों के बराबर है।

शर्मा ने कहा कि गत सरकार ने युवाओं को जो नौकरियां दीं, उनमें से 65 हजार भर्तियां हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की थीं। हमारी सरकार द्वारा 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 1 लाख 55 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

'हर साल हजारों करोड़ रु. दान कर देते हैं भारतीय'

नई दिल्ली, 21 फरवरी। भारत में रहने वाले लोग हर साल हजारों करोड़ रुपये दान में दे देते हैं। इस बात का खुलासा "हाउ इंडिया गिव्स" रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में हुआ है।

इसमें व्यक्तिगत दान का 45.9 प्रतिशत हिस्सा धार्मिक संगठनों को जाता है। 41.8प्रतिशत दान सीधे बेहद गरीब, जरूरतमंद व भिक्षा मांगने वालों को मिलता है। गैर-धार्मिक संगठनों तक सिर्फ 14.9 प्रतिशत दान पहुंचता है।

- "हाउ इंडिया गिव्स" रिपोर्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार सबसे ज्यादा 45.9 प्रतिशत दान धार्मिक संगठनों को जाता है और 41.8 प्रतिशत सीधे जरुरतमंदों को दिया जाता है। गैर धार्मिक संगठनों को 14.9 प्रतिशत दान जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में दान का सबसे बड़ा आधार आम घर हैं। कुल घरेलू दान का अनुमान हर साल 54 हजार करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 68 प्रतिशत लोगों ने किसी न किसी रूप में देने की बात कही।

रोहित पवार ने नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग की

अजित पवार के भतीजे रोहित ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की

मुंबई, 21 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की है। रोहित पवार ने तर्क दिया है कि महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जान लेने वाली विमान दुर्घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मंत्री का पद से हटना आवश्यक है।

- पवार ने कहा जिस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके प्रमोटर्स से मंत्री राममोहन नायडू के निकट सबंध हैं, उन्हें हटाए बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में रोहित पवार ने 'हितों के टकराव' का गंभीर मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस विमानन कंपनी (वीएसआर वेंचर्स) का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके प्रमोटरों और नागरिक उड्डयन मंत्री की पार्टी (टीडीपी) के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्घटना से ठीक पहले विमान के डेटा और उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि संबंधित कंपनी के रिकॉर्ड और सुरक्षा मानकों की जांच में पारदर्शिता की कमी है।

रोहित पवार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है। चूंकि यह एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा चूक का मामला है, इसलिए इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस पत्र की प्रति भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है।

रोहित पवार ने शनिवार को अजित पवार के प्लेन क्रैश पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखाए।

उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था। उनके मुताबिक, दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे।

विमान में सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, जिससे आग भड़की। सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए।

जिस सीवीआर की हम बात कर रहे हैं, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, उसकी उस उड़ान में रिकॉर्डिंग क्षमता केवल 30 मिनट की थी। लेकिन यदि आप सरकारी नियमों को देखें, तो डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) की आवश्यकता दो घंटे की रिकॉर्डिंग की है। तो अगर विमान का सीवीआर केवल 30 मिनट रिकॉर्ड कर सकता था, जबकि नियम दो घंटे का है, तो उस विमान का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? यह बात हम सभी जानना चाहते हैं।

यह दुर्घटना से पहले के अंतिम 30 मिनटों का रिकॉर्ड है, यानी यह आखिरी दर्ज किया गया हिस्सा है। उन अंतिम 30 मिनटों में क्या हुआ, इसकी जानकारी केवल सीवीआर से ही मिल सकती है। कहा जा रहा है कि सीवीआर क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं है।

ममता बनर्जी के साथ मंच पर नज़र आए भाजपा सांसद नागेन रॉय

रॉय ने केन्द्र पर बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया

कोलकाता, 21 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद नागेन रॉय उर्फ अनंत महाराज राजबंशी समुदाय के नेता हैं। उनको शनिवार को शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस समारोह में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं।

महाराज के संबंध हाल के महीनों में भाजपा के साथ तनावपूर्ण रहे हैं। मंच पर बैठे और वरिष्ठ मंत्रियों व टीएमसी नेताओं ने आरोप बिस्वास और इंद्रनील सेन के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, आपकी मौजूदगी से हमें सम्मान मिला है। खुश रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री के रूप में बनर्जी का यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलों को बढ़ाते हुए महाराज ने बाद में पत्रकारों से कहा, केन्द्र सरकार ने हमारे समुदाय के साथ भेदभाव किया है, जो बड़ी उम्मीदों के साथ भारत में शामिल हुआ था। मौजूदा सरकार सहित कई सरकारों की ओर से कई वर्षों तक हमारे क्षेत्र की लगातार उपेक्षा की गई है। जब उन्हें याद दिलाया गया कि वह केन्द्र की सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या मैं भारत के विकास के बारे में बात नहीं कर सकता? क्या हम देश का हिस्सा नहीं हैं?

- अटकलें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल का दौर तेज हो सकता है।

अखिलेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हों तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कपड़े उतारकर प्रदर्शन ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के कारण जो हंगामा हुआ है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार झूठ बोलती है या धोखा देती है, यह तो अलग बात है। हम अपने इंटरनल लड़ लेंगे, लेकिन कांग्रेस को उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जिससे फौरन डेलिगेट्स और फॉरेन कंट्री की नज़र में देश का अपमान हो। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चीन के रोबोट पर सरकार को घेरा, लेकिन कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के समर्थन से हाथ खींचे हैं। सपा मुखिया भी वैश्विक मंच पर देश की छवि खराब करने वाले विरोध-प्रदर्शन से सहमत नहीं हैं, भले ही विरोध-प्रदर्शन करने वालों से उनका राजनीतिक गठबंधन हो।

'भारत के साथ ट्रेड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रमेश ने कहा कि 2 फ़रवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते की घोषणा करते हुए कहा था कि वे इससे खुश हैं और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम की समय-रेखा महत्वपूर्ण है।

जयराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से, मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित निर्णय में, ट्रंप के वैश्विक टैरिफ़ को अवैध ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति ने व्यापक शुल्क लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया।

रमेश ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को दिसंबर से ही संभावित फैसले की जानकारी थी और यह आशंका थी कि टैरिफ़ रद्द हो सकते हैं, तो फिर इतनी जल्दबाज़ी में समझौता क्यों किया गया।

उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत टैरिफ़ आयात पर 150 दिनों के लिए लागू होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि समझौते के ढांचे में यह प्रावधान है कि किसी भी पक्ष द्वारा बदलाव की स्थिति में दोनों देश अपनी प्रतिबद्धताओं में संशोधन कर सकते हैं।

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में जब अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति की घोषणा की थी, तब ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ़ को हटा दिया था। इसके साथ ही, वॉशिंगटन ने नई दिल्ली पर पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ़) 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था।

राहुल ने कई इन्टरव्यु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डोटासरा के बीच कड़े मतभेद की चर्चाएँ भी रही हैं। गौरतलब है कि 2007 से राहुल गांधी एनएसयूआई और युवा कांग्रेस अध्यक्ष पदों के लिए साक्षात्कार, चयन और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। लेकिन इस कवायद से अभी तक कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता उभरकर सामने नहीं आया है, जबकि अतीत में युवा कांग्रेस से प्रशिक्षण पाकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित हुए थे।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

दुष्कर्म एवं पॉक्सो कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्य स्वामी मुकुदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है

प्रयागराज, 21 फरवरी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण आरोप के मामले में एडीजे दुष्कर्म एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। एडीजे पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी थाना पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने न्यायालय में 173 (4) के तहत वाद दाखिल करके एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। इस संबंध में 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज हुए थे। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस की रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज अदालत के एक आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

- इधर स्वामी अविमुक्तश्वरानंद ने कहा एफआईआर हो और जांच हो तभी सच्चाई सामने आएगी।

शंकराचार्य ने अदालत के इस आदेश को उचित बताया है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज होने पर ही जांच प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद गवाही दर्ज की जाएगी। तभी उनके खिलाफ दर्ज झूठे मामले की सच्चाई सबके सामने आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने वाले जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जा सकेगा। इसलिए यह कदम आवश्यक है। शंकराचार्य ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें अधिक समय न लिया जाए, क्योंकि कई लोग इस मामले पर नजर रख रहे हैं। गवाही जल्द से जल्द दर्ज की जानी चाहिए। निर्णय भी शीघ्र लिया जाना चाहिए।

दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट

नई दिल्ली, 21 फरवरी। दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस खुफिया जानकारी के बाद राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) दिल्ली में आईईडी हमले की साजिश रच रहा है।

- खुफिया जानकारी मिली है कि लश्करे तैयबा दिल्ली में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा है।

सूत्रों के अनुसार, आतंकियों के निशाने पर ऐतिहासिक लाल किला स्थित मंदिर और उसके आसपास का इलाका हो सकता है।

खासकर भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक स्थित प्रमुख मंदिर को लेकर इनपुट मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी विशेष स्थल का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है।

5 लाख रु. की रिश्वत लेते पकड़े गए भाजपा विधायक

नई दिल्ली, 21 फरवरी। कर्नाटक के शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चंद्रू लमानी को कर्नाटक लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि वे 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए।

अधिकारियों ने बताया कि लमानी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था, फिर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में उनके दो पर्सनल असिस्टेंट को भी हिरासत में लिया गया है।

लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, यह रिश्वत कथित तौर पर गडग जिले में छोटे सिंचाई विभाग के एक प्रोजेक्ट से जुड़ी मंजूरी दिलाने के लिए मांगी गई थी। इस काम के तहत सड़क के दोनों तरफ एक रिटेनिंग वॉल (सहायक दीवार) बनानी थी।

शिकायत करने वाले गडग के क्लास-1 कॉन्ट्रैक्टर विजय पुजार से जब कथित तौर पर प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी लेने के लिए 11 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद उन्होंने एंटी-करप्शन अधिकारियों से संपर्क किया।

एआई इम्पैक्ट का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोरिया, इजरायल, ईरान, ब्राज़ील, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, यूएई, स्पेन सहित, पड़ोसी देश म्यांमार, श्रीलंका ने हस्ताक्षर किये हैं। 86 देशों के साथ दो संगठन, यूरोपीय यूनियन और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास फंड ने भी हस्ताक्षर किए हैं। घोषणा पत्र के तहत आधारभूत संसाधनों तक किफायती पहुंच सुनिश्चित कर स्थानीय नवाचार तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि विकासशील समाज अपनी जरूरतों के समाधान स्वयं विकसित कर सकें। विभिन्न देशों में सफल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगों को साझा और विस्तारित करने की सुविधा के लिए साझा मंच बनाया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर विकास संबंधी चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा।

क्या "रैसिप्रोकल टैरिफ" से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेन-देन ढांचे में उपलब्ध सूक्ष्म डेटा के कारण भुगतान श्रृंखला का निर्धारण करना अत्यधिक कठिन नहीं होना चाहिए।

यह मामला एक बात स्पष्ट करता है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ का भुगतान निर्यातकों या विदेशी संस्थाओं ने नहीं किया; पहले इसे अमेरिकी आयातक कंपनियों ने चुकाया और अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं ने ऊँची कीमतों के रूप में इसका बोझ उठाया।

अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा जारी टैरिफ पश्चात व्यापार आँकड़ों के अनुसार, ऊँची कीमतों के बावजूद, अमेरिकी मांग में उल्लेखनीय कमी नहीं आई। इसका कारण यह है कि अमेरिका अब उन छोटे उपभोक्ता उत्पादों का अधिकांश उत्पादन स्वयं नहीं करता, जो राष्ट्रपति के टैरिफ आदेशों के दायरे में आए थे।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने केवल इतना कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद ही भारत पर संभावित प्रभावों का आकलन किया जाएगा। आगे की कोई भी कार्रवाई उसके बाद की जाएगी।

इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापार कानूनों के एक अन्य प्रावधान का उपयोग करते हुए भुगतान संतुलन घाटे के मद्देनज़र सभी आयातों पर 10 प्रतिशत का समान शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। क्या इसका अर्थ यह है कि अमेरिका में आने वाले सभी आयात, उनके मूल देश की परवाह किए बिना, 10 प्रतिशत प्रवेश शुल्क के अधीन होंगे?

यदि ऐसा होता है, तो अमेरिका और विभिन्न व्यापारिक देशों के बीच अलग-अलग टैरिफ समझौतों और व्यवस्थाओं का महत्व कम हो सकता है और 10 प्रतिशत का एकसमान शुल्क लागू होगा। एक अर्थ में यह भारत के लिए प्रतिकूल हो सकता है।

कई देशों को पहले कहीं अधिक ऊँचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा था, जिससे तुलनात्मक रूप से भारतीय निर्यात को लाभ मिलता था, क्योंकि भारत पर 18 प्रतिशत का टैरिफ दायित्व था। उदाहरण के लिए, चीन पर कुल मिलाकर कहीं अधिक ऊँचे टैरिफ़ लगाए गए थे। भारत के कुछ अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर भी उच्च दरें लागू थीं।

किसी भी स्थिति में, अन्य देशों की तुलना में भारत का वस्तु-निर्यात बहुत बड़ा नहीं है, चाहे दावे कुछ भी किए जाएँ। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सेवा-निर्यात को बनाए रखने में है। यह क्षेत्र अभी तक टैरिफ युद्धों से मुख्यतः अछूता रहा है। जब तक यह स्थिति बनी रहती है, यह भारत के हित में है।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने इसे केवल एक संदर्भ ग्रंथ नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम बताया।

उन्होंने कहा कि यह पहल संविधान को लोगों तक उनकी अपनी भाषाओं में पहुंचाने का माध्यम बनेगी, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी और संवैधानिक जागरूकता और अधिक सुदृढ़ होगी।

योगी आदित्यनाथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गौरतलब है कि "यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण" पहले ही राज्य सरकार को जापान सिटी और सिंगापुर सिटी विकसित करने का प्रस्ताव भेज चुका है। योगी अपनी इस यात्रा के दौरान, शीर्ष नेतृत्व और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर इन प्रोजेक्टों के लिए निवेश प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की छवि में बंधे रहने के बजाय, मुख्यमंत्री अब कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "गुजरात मॉडल" विकास अभियान से प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि 2013 में मोदी ने विकास के "गुजरात मॉडल" को सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट किया था। अगला आम चुनाव होने में अभी तीन वर्ष से अधिक शेष समय है, लेकिन भाजपा के भीतर मोदी के उत्तराधिकारी की संभावित दौड़ तेज होने से पहले योगी खुद को पीछे रहने देना नहीं चाहते। हाल के सप्ताहों में योगी सरकार ने राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति में सुधार को प्रमुखता से उजागर किया है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सात वर्षों में राज्य में बैंक ऋण प्रवाह और औद्योगिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्रेडिट-डिपॉज़िट अनुपात बढ़ा है और कुल ऋण वितरण दोगुना हुआ है। आँकड़े बताते हैं कि बैंकों में जमा धन का बड़ा हिस्सा, अन्य किसी क्षेत्र के बजाय, अब ऋण के रूप में राज्य के भीतर ही लगाया जा रहा है।

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 2017 से 2024 के बीच औद्योगिक ऋण लगभग 82,000 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 1.68 लाख करोड़ रुपये, अर्थात दोगुना हो गया है। राज्य के अधिकारी इसे मैन्यूफैक्चरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी का संकेत बता रहे हैं।

जापान और सिंगापुर दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री भारतीय प्रवासी समुदाय, उद्योग विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित किया जा सके और सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। टोक्यो में "जापान-उत्तर प्रदेश साझेदारी: विनिर्माण, गतिशीलता और प्रौद्योगिकी" विषय पर एक सम्मेलन भी प्रस्तावित है।

भारत पर अमेरिकन टैरिफ 18 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सहमत हुए हों।

लेकिन, वाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप प्रशासन आगे चलकर "अधिक उपयुक्त या पूर्व-निर्धारित टैरिफ़ दरें लागू करने" के विकल्प तलाशेगा।

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति की घोषणा की थी। इससे पहले, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ़ को हटाया था और नई दिल्ली पर रैसिप्रोकल शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था।

अब 10 प्रतिशत की नई वैश्विक दर, जो दुनिया के सभी देशों पर लागू होगी, लागू होने के बाद, अमेरिका में आयातित भारतीय वस्तुओं पर पहले तय 18 प्रतिशत टैरिफ़ लागू नहीं रहेगा।

लेकिन धारा 122 के तहत लगाए गए ये टैरिफ़ 150 दिनों के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि कांग्रेस इन्हें बढ़ाने के लिए मतदान न करे। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि यद्यिप समय-सीमा स्पष्ट है, लेकिन राष्ट्रपति इन उपायों को समाप्त होने दे सकते हैं और फिर नए भुगतान संतुलन आपातकाल की घोषणा कर पुनः लागू कर सकते हैं।

ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह राष्ट्रपति की व्यापार नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उनके चुनाव अभियान और एजेंडे का केन्द्रीय हिस्सा रही है।

इसी बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर टैरिफ में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए घोषणा की कि अब से तुरंत प्रभाव से दुनिया के सभी देशों से होने वाले आयात पर लगने वाला टैरिफ 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया जाएगा।

जेवर में सेमीकंडक्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य पर तीव्र गति से कार्य कर रहा है। उन्होंने लाल किले से दिए अपने संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के पास रुकने या ठहरने का समय नहीं है। वर्ष 2026 की शुरुआत से ही देश ने विकास की रफ्तार और तेज कर दी है।

उन्होंने बताया कि भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 10 फैब्रिकेशन और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से चार शीघ्र उत्पादन शुरू करने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20वीं सदी में जिस देश के पास तेल था, वही समृद्ध माना जाता था, लेकिन 21वीं सदी में वही शक्ति छोटी सी चिप और उससे जुड़ी स्किल एवं मटीरियल के पास है।

कोरोना महामारी के दौरान चिप सप्लाई चेन में आई बाधाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने उस संकट से सीखकर आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908